हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 78 | देहरादून, शनिवार, 10 सितंबर, 2022 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 08

स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स कांन्क्लेव में शामिल होंगी मंत्री रेखा आर्या 3

उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तान्तरित

कैबिनेट ने किया प्रस्ताव पारित

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 9 सितम्बर। उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तान्तरित करने के सम्बंध में आज कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश हैं कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठाएगी।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने इन भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

■ भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठाएगी: सीएम पुष्कर सिंह धामी

सीएम ने भविष्य की परीक्षाओं का भी एडवांस कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश है कि वर्तमान विज्ञापित पदों के साथ-साथ राज्य सरकार के सभी विभाग एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने यहां सीधी भर्तियों के रिक्त पदों की सूची बनाते हुए आयोग को उपलब्ध कराएं जिससे भविष्य की

परीक्षाओं का भी एडवांस कैलेंडर जारी किया जा सके।वे समस्त परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किसी भी चरण की परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित कर दिया गया है, किन्तु चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है. उन परीक्षाओं की अवशेष कार्यवाही उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जायेगी। वे समस्त परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं तथा कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है; उनमें लोक सेवा आयोग की परिधि में जाने के पश्चात् पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने की दशा में अभ्यार्थियों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध है

शीघ्र से शीघ्र परीक्षाएं कराकर युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता: सीएम

युवाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र से शीघ्र परीक्षाएं कराकर युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। युवा बेरोजगारों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिए सरकार कृतसंकल्प है।

हरिद्वार पंचायत चुनाव के बावजूद धड़ल्ले से किए जा रहे हैं तबादले : गरिमा मेहरा दसौनी

देहरादून 9 सितम्बर। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने इन तबादलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरिद्वार जिले में आचार संहिता लग चुकी है ऐसे में यह तबादले चुनाव बाद भी कराए जा सकते थे। दसोनी ने कहा कि राज्य में जो सरकार पदासीन है ना ही उसका लोकतंत्र में कोई विश्वास है ना ही संविधान में।दसौनी ने आपत्ति जताते हुए कहा की हरिद्वार में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं नामांकन गतिमान हैं ऐसे वक्त पर यह तबादले राज्य निर्वाचन आयोग को ठेंगा दिखाने जैसा हैदसोनी ने कहा यूपीसीएल सरकार का ही हिस्सा है ऐसे में अपेक्षा की जाती है की राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए इन सभी तबादलों को निरस्त किया जायेगा और आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के साथ सख्तायी से पेश आया जाएगा।

'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' में ऑनलाइन जुड़े गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि)

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 9 सितम्बर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' की शुरुआत की। जिसके अन्तर्गत 'नि-क्षय 2.0' पोर्टल को शुरू किया गया। इस अभियान के अन्तर्गत भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) भी वर्चुअल रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि 'नि-क्षय 2.0' का उद्देश्य टीबी मुक्त भारत के लिए जन भागीदारी बढ़ाना है। उन्होंने सभी राज्यपालों/उपराज्यपालों से कहा कि स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य संस्थाओं, एन.जी.ओ व अन्य स्टेक होल्डर के साथ मिलकर इस अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में बढ़ाया जाय। उन्होंने कहा कि विश्व में टीबी के कुल रोगियों की संख्या कुल 25 प्रतिशत से अधिक भारत में है जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए सभी लोगों को मिलकर कार्य करना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए लोगों में टीबी के बारे में जागरूकता पैदा करनी होगी। उन्हें यह बताना होगा कि इस बीमारी की रोकथाम और कारगर इलाज संभव है। सरकार द्वारा इस बीमारी का इलाज निःशुल्क किया जाता है । हमें लोगों को बीमारी से निपटने के उपाय बताने होंगे। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए पोषण संबंधी सहायता, जीवन-यापन जैसे निर्धारकों में सहयोग हेतु बहुक्षेत्रीय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत नि-क्षय मित्र द्वारा टीबी रोगियों को उपचार अवधि में अतिरिक्त पोषण, जांच एवं उपचार आदि में सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर सचिव राज्यपाल डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, सचिव (प्रभारी) स्वास्थ्य डॉ. आर.राजेश कुमार, अपर सचिव राज्यपाल स्वाति एस.भदौरिया, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. शैलजा भट्ट, निदेशक एन.एच.एम डॉ. सरोज नैथानी, राज्य क्षय निवारण अधिकारी डॉ. एस.के.झा, कार्यक्रम अधिकारी टीबी डॉ. पंकज सिंह, टीबी एसोसिएशन उत्तराखण्ड की सचिव पूनम किमोठी और समस्त जिलों से मुख्य चिकित्साधिकारी आदि उपस्थित रहे।

बद्रीनाथ जा रही कार के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हादसा ब्रह्मपुरी श्रीराम तपस्थली के पास हुआ पुलिस ने कहा कि बद्रीनाथ की ओर जा रहे चार लोगों की शुक्रवार को 50 मीटर गहरी खाई में गिर कर मौत हो गई और कई घायल हो गए। कार चालक रविंद्र सिंह पुत्र ज्ञान सिंह उखीमठ जिला रुद्रप्रयाग का रहने वाला है,रविंद्र सिंह के मुताबिक शुक्रवार सुबह हरिद्वार से 5 यात्रियों को लेकर बदरीनाथ धाम के लिए रवाना हुआ था. ब्रह्मपुरी के पास उसकी

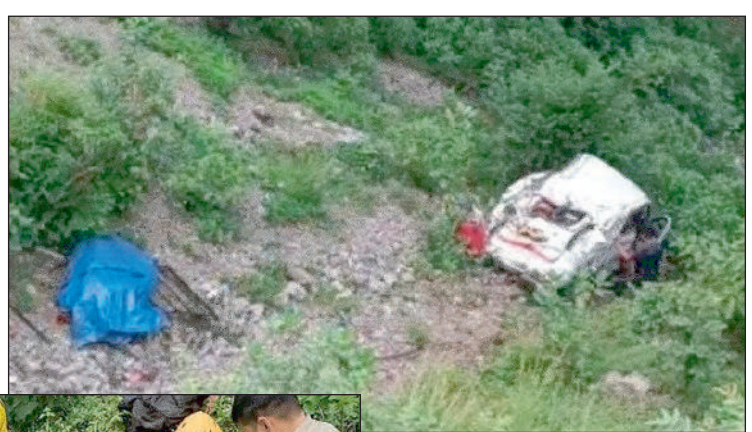

कार अचानक अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी. मुनि-की-रेती थाने के एसएचओ रितेश शाह ने बताया कि हादसा ब्रह्मपुरी श्रीराम तपस्थली के पास हुआ। वाहन हरिद्वार से हिमालय मंदिर जा रही थी और उसमें सवार लोग मुंबई के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त कार में ऊखीमठ निवासी चालक रविंद्र सिंह समेत छह लोग सवार थे.पुलिस ने कहा कि तीन शव बरामद कर लिए गए हैं और तीन घायलों को ऋषिकेश के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

क्या आप जानते है हिरासत और गिरफ्तारी में क्या होता है अंतर?

आलम गाँधी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

अगर आप किसी अपराध में लिप्त पाए जाते हैं या ऐसे किसी अपराध का पुलिस को आप पर शक होता है तो आपकी गिरफ्तारी होती है. कई मामलों में पुलिस आरोपी को हिरासत में ले लेती है. यहां यह जानना जरूरी है कि हिरासत और गिरफ्तारी में अंतर होता है तो चलिए जानते हैं इस खबर में -

अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जब किसी मामले में किसी आरोपी को न्यायिक हिरासत दी जाती है और किसी को पुलिस हिरासत. कहीं गिरफ्तारी होती है और कहीं हिरासत. अगर आपको भी लगता है कि दोनों एक ही बात हैं तो यह जानकारी होना जरूरी है. जानें कितने प्रकार की होती है कस्टडी और क्या होता है पुलिस कस्टडी व ज्यूडिशियल कस्टडी में अंतर-

क्या होती है कस्टडी

कस्टडी यानी हिरासत शब्द का अर्थ है सुरक्षात्मक देखभाल के लिए किसी को पकड़ना. हिरासत और गिरफ्तारी पर्यायवाची नहीं हैं. हर गिरफ्तारी में हिरासत होती है, लेकिन हर हिरासत में गिरफ्तारी नहीं होती है. किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है यदि वह अपराध करने का दोषी हो या उस पर संदेह हो. लेकिन हिरासत का मतलब किसी की रक्षा करना या उसे अस्थायी रूप से जेल में रखना होता है. जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे हिरासत में रखा जाता है.

कस्टडी दो तरह की होती है

- पुलिस कस्टडी- ज्यूडिशियल कस्टडी

पुलिस कस्टडी (पुलिस हिरासत)

पुलिस कस्टडी के दौरान आरोपी से अपराध के बारे में पूछताछ या जांच-पड़ताल की जाती है. पुलिस हिरासत के दौरान पुलिसआरोपी को घटनास्थल पर ले जाती है और जांच में मिलने वाले सबूतों को अपने कब्जे में ले लेती है. गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का नियम है जो कि CRPC की धारा 167 के तहत किया जाता है. मजिस्ट्रेट यह फैसला करते हैं कि आगे की जांच या पूछताछ की आवश्यकता है या नहीं. मजिस्ट्रेट आरोपी को 15 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दे सकते हैं. गंभीरता और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर इसे 30 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है.वह पुलिस हिरासत से ज्यूडिशियल हिरासत में बदलने का आदेश भी दे सकते हैं.

ज्यूडिशियल कस्टडी (न्यायिक हिरासत)

जब किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रखा जाता है तो इसे ज्यूडिशियल कस्टडी कहा जाता है. मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही आरोपी को निश्चित अवधि के लिए जेल में रखा जाता है. आरोपी या संदिग्ध आरोपी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाता है. उसे जनता की नजरों से दूर रखा जाता है ताकि उसे जनता या समाज के किसी वर्ग द्वारा किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या उत्पीड़न से बचाया जा सके. यदि कोई व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है और जांच अभी भी चल रही है तो पुलिस को 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर करना होता है.

क्या होता है पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में अंतर

1) पुलिस कस्टडी में आरोपी को पुलिस थाने में कार्यवाही के कारण रखा जाता है और न्यायिक हिरासत में आरोपी को जेल में रखा जाता है.

2) पुलिस कस्टडी की अवधि 24घंटे की होती है जबकि न्यायिक हिरासत में ऐसी कोई अवधि नहीं होती है.

3) पुलिस कस्टडी में रखे आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है. न्यायिक हिरासत में आरोपी को तब तक जेल में रखा जाता है जब तक कि उसके खिलाफ मामला अदालत में चल रहा हो या अदालत उसे जमानत ना दे.

4) पुलिस कस्टडी में पुलिस आरोपी को मार-पीट सकती है ताकि वह अपना अपराध कबूल कर ले, लेकिन अगर आरोपी सीधे कोर्ट में हाजिर हो जाता है तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है और वह पुलिस की पिटाई से बच जाता है. यदि पुलिस को किसी तरह की पूछताछ करनी हो तो सबसे पहले न्यायधीश से आज्ञा लेनी पड़ती है.

5) पुलिस कस्टडी पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के अंतर्गत आती है, जबकि न्यायिक कस्टडी में आरोपी न्यायधीश की सुरक्षा के अंतर्गत आता है.

जीवन में असली सांपों से ज्यादा इन सांपों से बचना चाहिए, ये सांप बहुत जहरीले होते हैं

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हमें बचपन से ही सांपों से सावधान रहने की बात कही गई है। हमें बताया जाता है कि सांप बहुत जहरीले होते हैं। इनके ज़हर से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। दरअसल हमारे जीवन में सिर्फ वही सांप नहीं होते आपको बता दे ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में तभी सफल हो सकता है जब वह न केवल अच्छी संगत में रहता है बल्कि अच्छे और बुरे लोगों को पहचानने की सच्ची परीक्षा भी रखता है। कई बार व्यक्ति की अच्छाई के कारण वह अपने आसपास के लोगों को सही देखता है, लेकिन सब एक जैसे हो ऐसा मुमकिन तो नहीं है।

जीवन में तरक्की के लिए बुरे लोगों की पहचान बहुत जरूरी है, नहीं तो जातक की खुशियां बर्बाद हो जाती है, परिवार में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। आज टीवी न्यूज वायरस आपको ऐसे सांपों के बारे में बताने जा रहा है जिससे आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए।

आस्तीन के सांप वाले दोस्त

हर कोई जानता है कि उनकी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं है। कभी-कभी एक दोस्त के रूप में आप अपने ही दुश्मन को खड़ा कर रहे होते हैं। आज के समय में सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। ये लोग चेहरे पर सच्चाई का झूठा मुखौटा पहनकर घूमते हैं। उन्हें मोर्चे पर आपसे ज्यादा सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन वे वापस जाते ही आपको गाली देने लगते हैं। चाणक्य ने मित्रों के चयन के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उनका कहना है कि अगर आपकी लिस्ट में कोई ऐसा दोस्त है, जो इधर-उधर ऐसा करता है तो तुरंत उससे दूरी बना लें।

तेज-तर्रार नौकर जहरीला सांप

नौकरों के चयन पर जोर दिया गया है। कहा जाता है कि सांप चालाक और लालची नौकर से बेहतर होता है। सांप तभी काटता है जब कोई उसे नुकसान पहुंचाता है, लेकिन लालची नौकर मालिक के पैसे पर कभी भी झूला झूल कर कोई भी घोटाला कर सकता है। सेवक स्वामी के मुख पर ईमानदार होते हैं लेकिन पीठ पीछे जहरीले होते हैं। वे मालिक के नाम का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नौकरों को कभी भी काम पर नहीं रखना चाहिए।

धूर्त पत्नी सांप से भी ज्यादा खतरनाक

कहते हैं जिंदगी के सफर में सच्चा और सच्चा साथी मिल जाए तो जिंदगी की राह जो भी हो, वो आसानी से पार हो जाती है. लेकिन धोखेबाज और दुष्ट स्त्री यदि किसी की पत्नी बन जाए तो उसके जीवन से सुख समाप्त हो जाता है। दुष्ट स्त्री न तो अपने पति का और न ही परिवार का सम्मान करती है। वह किसी की इज्जत नहीं करती। कहते हैं कि धूर्त पत्नी के साथ रहना मृत्यु से बढ़कर है। आपको समय रहते ऐसी महिला से दूरी बना लेनी चाहिए वरना वह आपकी जिंदगी को नर्क बना सकती है।

एप्पल ने लॉन्च किया 2022 का सबसे महंगा iPhone , जानिए क्या है कीमत

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

IPhone - 5 वर्षों में पहली बार - एक बिल्कुल नया डिस्प्ले मिलता है जिसमें एक गोली के आकार का डिज़ाइन होता है। एप्पल ने iPhone 14 Pro सीरीज के साथ पायदान को हटा दिया है। एप्पल iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max: भारत की कीमत और उपलब्धताग्राहक iPhone 14 Pro को 129900 रुपये में और iPhone 14 Pro Max को 139900 रुपये में खरीद सकते हैं। iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max 128GB, 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज में डीप पर्पल, सिल्वर, गोल्ड और स्पेस ब्लैक में उपलब्ध होंगे। क्षमताएं।भारत और 30 अन्य देशों और क्षेत्रों के ग्राहक 9 सितंबर से iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max का प्री-ऑर्डर कर सकेंगे और फोन 16 सितंबर से उपलब्ध होंगे।नए डिस्प्ले में iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max 6.1-इंच और 6.7-इंच डिस्प्ले के साथ आते हैं। डिस्प्ले 1600 निट्स ब्राइटनेस लेवल प्रदान करता है और 2000 निट्स तक जा सकता है। एप्पल का कहना है कि कोई अन्य स्मार्टफोन इन ब्राइटनेस लेवल की पेशकश नहीं करता है।गोली के आकार का कटआउट वह है जिसे Apple डायनेमिक आइलैंड कहता है, जिसका उपयोग बहुत कुछ करने के लिए किया जा सकता है। . डायनेमिक आइलैंड में,

उपयोगकर्ता बैटरी स्तर देख सकते हैं, और अन्य चीजों के अलावा ऐप्पल मैप्स से दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।एपल का कहना है कि थर्ड पार्टी ऐप्स भी यूजर्स को ज्यादा अलर्ट दिखाने के लिए उस स्पेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। डायनेमिक आइलैंड आईफ़ोन के लिए बिल्कुल नया अनुभव लेकर आया है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर को पहली बार डिस्प्ले के अंदर लगाया गया हैApple ने पहली बार iPhone 14 और iPhone 14 Pro के साथ ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले भी पेश किया है।

स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स कांन्क्लेव में शामिल होंगी मंत्री रेखा आर्या

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 10 सितम्बर , उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या दो दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद,गुजरात में आयोजित स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी(State S &T) मिनिस्टर्स कांन्क्लेव में शिरकत करेंगी.यह आयोजन अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित किया जायेगा.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया की इस कांन्क्लेव में सभी राज्यों के मिनिस्टर्स प्रतिभाग करेंगे.उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार वक्त करते हुए कहा की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें कांन्क्लेव में समन्वय और प्रतिभाग किये जाने हेतु नामित किया है.

साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा की उत्तराखंड ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से कार्य किया है उसे रखा जाएगा और साथ ही हमें केंद्र सरकार से किन-किन चीजों की आवश्यकता है उसकी मांग की जाएगी. उन्होंने कहा की निश्चित रूप से यह कांन्क्लेव उत्तराखंड की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सार्थक सिद्ध होगा.आपको बता दें की यह दो दिवसीय कांन्क्लेव 10 और 11 सितम्बर को अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित किया जा रहा है

हरिद्वार पंचायत चुनाव के आखिरी दिन तीन नामांकन केंद्रों पर 258 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार भाजपा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है, दोनों दलों के नए प्रदेश अध्यक्षों की भी परीक्षा है, बसपा के आने से यह मुकाबला है. त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इन चुनावों को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इन चुनावों को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है. हरिद्वार में पंचायत चुनाव के लिए 26 सितंबर को मतदान और 28 को मतगणना होगी। इसी प्रकार हरिद्वार जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस, बसपा समेत अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कुल 258 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तीन दिनों में जिला पंचायत सदस्यों की 44 सीटों के लिए कुल 585 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। रिटर्निंग ऑफिसर बृजेश तिवारी ने बताया कि जिला पंचायत परिसर में तीन नामांकन केंद्रों पर 258 उम्मीदवारों ने

नामांकन पत्र दाखिल किया है।

जाने पूरी लिस्ट :

भाजपा समर्थित उम्मीदवारों में औरंगाबाद सीट से विमलेश चौहान, सलेमपुर महदूद द्वितीय सीट से मीनाक्षी, सलेमपुर महदूद प्रथम सीट से मंजू देवी, बुड्ढाहेड़ी सीट से प्रताप सिंह, गढ़मीरपुर सीट से अमित सैनी आदि ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों में कोटवाल आलमपुर सीट से शिवकांत सिंह, लक्सर सीट से बालेश्वर सिंह, लिब्बारेहड़ी सीट से सीपी सिंह, अलावलपुर सीट से आदेश कटारिया समेत अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बसपा से सलेमपुर महदूद प्रथम सीट से किरन, मेवड सीट से योगेश कुमार और अन्य ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्दलीय उम्मीदवार भी बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल कराने पहुंचे।

विरासत : मुरादें पूरी करता है मसूरी का ये पुराना कुआँ

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 10 सितम्बर , पहाड़ों की रानी मसूरी के हाथीपाँव में एक एतिहासिक कुआँ मौजूद है। प्रकृति की गोद में बने क़रीब दौ सौ साल पुराने इस कुँए को विशिंग वेल के नाम से जाना जाता है। 1829 के आस पास अंग्रेज़ आर्मी के एक आफ़िसर कर्नल विश ने मसूरी के हाथी पाँव में अपना घर बनवाया था। उस वक्त हाथी पाँव में पानी की इतनी दिक्क़तें थी कि खच्चरों पर पानी लाद कर यहाँ लाया जाता था। तब कर्नल विश ने तक़रीबन सात हज़ार फ़ीट की ऊँचाई पर यहाँ इस कुएँ का निर्माण कराया था। उन्हीं के नाम पर इसे विशिंग वेल कहा जाता है। अमूमन पहाड़ों में पानी के कुएँ इतनी ऊँचाई पर नहीं होते। प्रदेश के सभी हिल स्टशनों में ये पहला कुआँ है जो इतनी ऊँचाई पर अंग्रेज़ों ने बनाया था। मसूरी के लोगों के मुताबिक़ सर जार्ज एवेरेस्ट भी इसी कुएँ का पानी इस्तेमाल करते थे। क़रीब 192 साल बाद भी आज ये विशिंग वेल लोगों की ज़रूरतें पूरी करने का काम करता है। आज इस कुँए का पानी बहुत कम हो गया है मगर हाथी

पाँव,कलाउड एंड और जार्ज एवरेस्ट के लोग इसी कुएँ से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। मसूरी में मौजूद हाथीपाँव, जोर्ज एवरेस्ट, क्लाउड एंड समेत आसपास घूमने आने वाले पर्यटक इस कुएँ को देखने ज़रूर आते हैं। इस कुएँ को लेकर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें सिक्का या अँगूठी डालने पर मुरादें भी पूरी होती हैं। इसीलिए इसे विशिंग वेल भी कहा जाता है। हालाँकि कुछ लोग ये मानते हैं कि कर्नल विश के नाम पर इसका नाम विशिंग वेल पड़ा। ये कुआँ अपने इतिहास को संजोय इस कुएँ का पानी पिछले कुछ सालों में कम हुआ है। इसलिए लोग खासे चिंतित भी हैं कि ये एतिहासिक कुँआ कहीं ख़ुद इतिहास ना बन जाए।

उत्तराखण्ड शासन
आज़ादी का अमृत महोत्सव

"भारत रत्न"
पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त

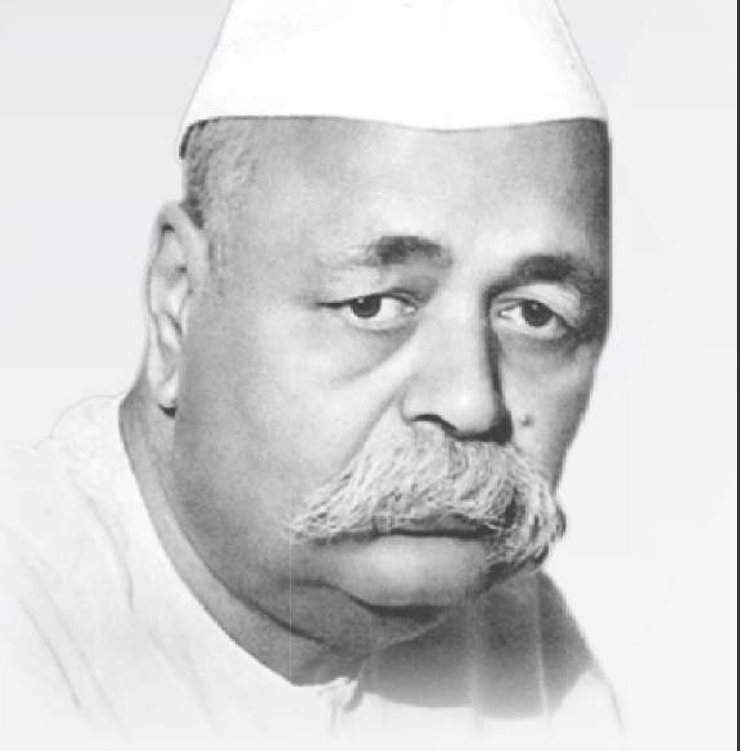

(10 सितम्बर 1887 - 7 मार्च 1961)

महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
एवं कुशल प्रशासक की जयंती
पर

उत्तराखण्ड वासियों
की ओर से शत शत नमन

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
www.uttarainformation.gov.in | DIPR_UK | UttarakhandDIPR | UttarakhandDIPR

हिमालय के प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने और संरक्षित करने का हर सम्भव प्रयास : मुख्यमंत्री

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में हिमालय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने हरि मंदिर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने हिमालय के संरक्षण हेतु शपथ दिलवाई एवं श्रीमद्भागवत गीता के ऊपर संक्षेप व सरल भाषा में लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय के प्राकृतिक जल स्रोतों धारों, नालों के अध्ययन, संरक्षण और संवर्धन के लिए एक कमेटी के गठन किए जाने की बात कही, जो विभिन्न प्रयासों से हिमालय के प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने और संरक्षित करने का हर सम्भव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमालय के संरक्षण में हम सभी की भागीदारी जरूरी है। सरकार के दोनों दायित्व तय हैं, जहां एक ओर हिमालय के संरक्षण के प्रति गंभीर रहना है, तो दूसरी ओर विकास के प्रति भी उतना ही दायित्व निभाना है, ताकि हिमालय का पर्यावरण सुरक्षित रहे और यहाँ के निवासियों की आर्थिकी भी। समूचे हिमालय से जुड़े राज्यों के लिए यहाँ की अलग भौगोलिक और स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल अलग विकास मॉडल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने नीति आयोग की बैठक में भी हिमालय के महत्वपूर्ण सरोकारों से जुड़े मुद्दों को साझा किया और इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव और प्रस्ताव साझा किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में सामाजिक विकास की आवश्यकता है, हमें इकॉलोजी एवं इकोनॉमी को साथ में रखते हुए कार्य करना होगा। हिमालय की जैव विविधता को संरक्षित करना है। जब हिमालय बचा रहेगा, तभी जीवन बचा रहेगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखण्ड वासियों के स्वभाव में है, हरेला जैसे पर्व, प्रकृति से जुड़ने की हमारे पूर्वजों की दूरगामी सोच का परिणाम है। पर्यावरण में हो रहे बदलावों, ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही जल, जंगल, जमीन से जुड़े विषयों पर समेकित चिंतन की जरूरत है। सामाजिक चेतना तथा समेकित सामूहिक प्रयासों से ही हम इस समस्या के समाधान में सहयोगी बन सकते हैं।

परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने हिमालय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पहाड़ी राज्य का प्रत्येक व्यक्ति हिमालय का प्रहरी है। हिमालय जैसे विराट भूभाग का संरक्षण ही असल मायनों में हमारे भविष्य का संरक्षण है। उन्होंने कहा गंगा, जलाशय, प्राकृतिक संसाधनों, ग्लेशियर का संरक्षण के साथ ही हिमालय का संरक्षण मुमकिन है। मां गंगा का अस्तित्व हिमालय एवं ग्लेशियर के अस्तित्व पर आधारित है, उन्होंने मुख्यमंत्री श्री धामी को एकल हनुमान सम्मान प्रदान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री धामी पर्यावरण के संरक्षण में हनुमान की तरह संकल्पित होकर अथक परिश्रम कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने कहा कि उत्तराखंड का वातावरण एवं पर्यावरण पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है। उन्होंने कहा यहां आने से नई ऊर्जा मिलती है। हिमालय के संरक्षण के साथ ही जीवनदायिनी मां गंगा का संरक्षण भी बेहद जरूरी है एवं पर्यावरण के संरक्षण में सभी की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने हर शुभ कार्य से पहले पौधारोपण एवं उत्तराखंड के साथ ही पूरे भारत को प्लास्टिक मुक्त किए जाने हेतु आग्रह किया।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एवं बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रकृति पर्यावरण के साथ ही हिमालय ग्लेशियर का संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वन विभाग जंगलों, प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के कार्य में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा हम सभी एवं आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण और हिमालय के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संकल्पबद्ध होना पड़ेगा ।

गौ-संरक्षण के लिए वह स्वयं एवं सरकार दोनों स्तरों पर प्रयास करेंगे : गणेश जोशी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

चम्पावत 10 सितम्बर, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को रामलीला मैदान में गणेश महोत्सव समिति लोहाघाट द्वारा आयोजित गौ-कथा कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की ओर उनका आशीर्वाद लिया और साथ ही प्रदेशवासियों की खुशहाली की मंगल कामना भी की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने गौ-कथा का भी श्रवण किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गौ-संरक्षण के लिए वह स्वयं एवं सरकार दोनों स्तरों पर प्रयास करेंगे।इस अवसर पर कथा वाचक व्यास आचार्य तारा दत्त जोशी, समिति के संयोजक गोविंद वर्मा, समिति के अध्यक्ष अमित, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, भाजपा की प्रदेश मंत्री हेमा जोशी, मंडल अध्यक्ष महेश बोरा, पूर्व जिला अध्यक्ष रामदत्त जोशी, वरिष्ठ भाजपा नेता हयात सिंह मेहरा सहित कई लोग उपस्थित रहे।

बुग्यालों में ट्री लाइन का बढ़ना राज्य में संकट का संकेत हो सकता है

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

बुग्याल किसे कहते हैं? उत्तराखंड राज्य में हिमालयी क्षेत्रों में स्थित पर्वतों की तलहटी में 3,300 मीटर और 4,000 मीटर की ऊंचाई में अल्पाइन प्रकार चरागाह भूमि या घास के विस्तृत मेदान मिलते है। इन घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में बुग्याल या पयार कहा जाता है।जलवायु परिवर्तन के कारण बुग्याल की ओर बढ़ती ट्री लाइन यानि पेड़ों की श्रृंखला हर साल औसतन करीब 15 से 20 मीटर ऊंचाई की ओर खिसक रही है। वृक्ष रेखा, हिमनद क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा और बढ़ती पर्यटन गतिविधियों के कारण बुग्याल का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हिमालयी क्षेत्र में स्थित बुग्यालों में मिट्टी का कार्बन कम होने के साथ-साथ जड़ी-बूटियों का दोहन भी बढ़ा है। सड़क निर्माण के मुद्दों ने भी उन्हें प्रभावित किया है। अगर समय रहते उनकी सुरक्षा की दिशा में काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में बुग्याल किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। आपको बता दें कि वृक्ष रेखा को टिम्बर लाइन भी कहा जाता है। वृक्ष रेखा हिमालयी राज्यों में विभिन्न ऊंचाईयों पर पाई जाती है। यह समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर पेड़ों की वृद्धि की अंतिम सीमा है। हिमालयी क्षेत्रों में वृक्ष रेखा के बाद पेड़ नहीं उगते हैं।शोध में पाया गया है कि उत्तराखंड में ट्री लाइन हर साल औसतन 15 से 20 मीटर ऊपर जा रही है। ट्री लाइन की ऊंचाई की ओर बदलाव के लिए तापमान और वर्षा प्रमुख कारक बन गए हैं।

राहुल गाँधी संग कदमताल कर रही हैं उत्तराखंड की ज्योति रौतेला

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून ,10 सितम्बर ,कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों सुर्खियों में है। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाले राहुल गांधी पर अब सबकी नजर है , क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस का यह सबसे बड़ा सियासी दांव है। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत , भूपेश बघेल और जयराम रमेश के साथ-साथ उत्तराखंड के हरीश रावत जैसे दिग्गज नेता भी उनके साथ चल रहे हैं।

तमिलनाडु में कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा में लोगों का हुजूम भी चल रहा है। इस पद यात्रा के दौरान राहुल गांधी कंटेनर में रात गुजार रहे हैं , कहा जा रहा है कि यह यात्रा पूरी तरह से एक पारंपरिक पदयात्रा की तरह है जिसमें आम लोगों को जोड़ने के लिए कांग्रेस के नेता आम आदमी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में कई नेता मीडिया में सुर्खियां भी बटोर रहे हैं और कई ऐसे नेता हैं जो देश के सबसे पुरानी पार्टी के दिग्गज नेता के साथ इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।

इस अभियान में किसी महिला का शामिल होना है यूं तो कोई अलग बात नहीं है लेकिन पहाड़ की वो महिला राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए पदयात्रा में जोशीले अंदाज़ में नजर आए तो मीडिया की लाइमलाइट में आना स्वाभाविक है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला इन दिनों राहुल गांधी के साथ इस पदयात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। एक तरफ जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने अनुभव और कौशल के साथ इस यात्रा में भागीदारी निभा रहे हैं तो वही अपनी पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ युवा नेत्री ज्योति रौतेला का जोश भी देखते बनता है।

यूं तो ज्योति रौतेला का ज्यादातर समय दिल्ली में पार्टी के संगठन और कार्यक्रमों में गुजरा है। लेकिन बीते कुछ समय से वह उत्तराखंड में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही है और एक बार फिर वायनाड से सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उनकी यह तस्वीरें बताती है कि किस तरह से महिला कांग्रेस में अपनी बड़ी पहचान बना चुकी ज्योति रौतेला का जज़्बा इस पदयात्रा में दिखाई दे रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश में भी उन्होंने जिस तरह से संगठन को सक्रिय बनाया है वैसे ही देश में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता पार्टी को एक बार फिर नए जोश और नए उम्मीद के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में कामयाबी दिलाएंगे। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में तमाम ऐसे कांग्रेसी नेता है जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला की सक्रिय भागीदारी पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार फिर कांग्रेस मुख्यधारा में राजनीति करती नजर आ रही है और महिलाओं का इस तरह से कदमताल करना हो सकता है कांग्रेस के लिए शुभ संकेत हो।

नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा : सचिव पर्यटन

आलम गांधी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 09 सितंबर , चारधाम यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए सचिव पर्यटन और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सीईओ सचिन कुर्वे ने उम्मीद जताई है कि इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। चारधाम तथा हेमकुंड साहिब में अब तक तैंतीस लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। जबकि सितंबर माह के लिए 05 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। केदारनाथ यात्रियों के लिए हेली शटल सेवाएं भी पुनः सामान्य हो गई हैं।सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने कहा कि इस वर्ष चार धाम यात्रियों की संख्या एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। पर्यटन विभाग देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता है और उन्हें अधिकतम सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सर्वथा प्रतिबद्ध है। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है अतः सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे चार धाम यात्रा पोर्टल पर पंजीकरण करने के उपरांत ही यात्रा आरंभ करें।गौरतलब है कि मानसून के अवसान के साथ ही उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। तीर्थयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर सिरसी फाटा तथा गुप्तकाशी से श्री केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध हैं। चारधाम के साथ ही हेमकुंड साहिब में अब तक कुल 33,47,287 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। जिसमें यमुनोत्री में लगभग 4 लाख, गंगोत्री में 5 लाख से अधिक, केदारनाथ में 11 लाख से अधिक, बद्रीनाथ में लगभग 12 लाख और हेमकुंड साहिब में लगभग 2 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा केदारनाथ दर्शन के लिए संचालित हेली शटल सेवाओं का अब तक एक लाख से अधिक तीर्थयात्री लाभ ले चुके हैं।

चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाईन पंजीकरण अनिवार्यः

बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए तीर्थयात्री और श्रद्धालु पर्यटन विभाग की वेबसाइट http://registrationandtouristcare.uk.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें। वहीं केदारनाथ हेली सेवा हेतु https://heliservices.uk.gov.in पर ऑनलाईन बुकिंग करें।

पाक की पाक प्रेम कहानी को मिली दुनिया भर में वाहवाही

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पडोसी मुल्क पाकिस्तान में भी लोग इश्क़ करते है , आशिकी के फूल खिलते हैं और बेमिसाल प्रेमी मिलते हैं। एक यूट्यूब चैनल पर इस कपल ने जब अपनी अजीबोगरीब प्रेम कहानी बताई.तो दुनियाभर के लोगों ने दिल से सुनी। ओकारा तहसील के दीपालपुर में रहने वाले इस कपल ने बताया कि उन्हें कैसे एक-दूसरे से प्यार हो गया. किश्वर बताती हैं कि वो अपने पति शहज़ाद की तहज़ीब और अदब पर अपना दिल हार बैठीं, जबकि शहज़ाद को वो बेहद खूबसूरत लगती थीं. जिस अस्पताल में किश्वर डॉक्टर थीं, उसमें शहज़ाद चाय परोसने और साफ-सफाई का काम करता था. शहज़ाद का कहना है कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन किस्मत को ये मंज़ूर था.

किश्वर ने खुद किया शहज़ाद को प्रपोज़ : आगाज पाक आपको जानकर हैरानी होगी की एमबीबीएस जैसी ऊंची पढ़ाई कर चुकीं किश्वर ने खुद शहज़ाद को प्रपोज़ किया था. वे कहती हैं कि दिखने में शहज़ाद क्लीनर या चायवाले जैसा नहीं लगता था और एक दिन उन्होंने उससे फोन नंबर मांगा और बातचीत शुरू कर दी. किश्वर ने खुद शहज़ाद को अपने कमरे में बुलाकर प्यार का इज़हार किया था. पहले तो वो चौंक गया और उसे बुखार तक आ गया. खैर, बाद में उन्होंने शादी कर ली. शादी के बाद किश्वर ने अस्पताल की नौकरी छोड़ दी क्योंकि समाज के ताने सहने पड़ते. अब डॉक्टर पास में ही क्लीनिक खोलने की योजना बना रहे हैं. लोग इस वीडियो के ज़रिये उन्हें उत्साहित कर रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं....

प्यार में तहज़ीब की अहमियत देखिये

सच्चे प्रेम की ये कहानी समाज में ऊंच-नीच के भेदभाव को झुठलाती है और ये बताने के लिए काफी है कि अलग प्यार की हुकूमत चले तो कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा. पाकिस्तान में एक डॉक्टर और चायवाले की अनोखी प्रेम कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई है और लोग इनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

क्या आपने कभी अमरूद की पत्ती की चाय पी है? जाने इसके फायदे

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पके हुए, कटे हुए अमरूद को चुटकी भर नमक और मिर्च पाउडर के साथ छिड़क कर खाने से बहुत पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। एक समय था जब यह घर पर मेरा दैनिक नाश्ता था, और हम अपने बाग़ से अमरूद के पेड़ से फल तब तक तोड़ते थे जब तक वो पेड़ पूरी तरह से खली न होजाए।माना जाता है कि अमरूद, एक उष्णकटिबंधीय फल है जिसकी उत्पत्ति मध्य अमेरिका में हुई थी, माना जाता है कि 17 वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था। कई किस्मों में आने वाले ये फल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।

कई अध्ययनों में दावा किया गया है कि अमरूद रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, मधुमेह को नियंत्रित करने, दिल के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, वजन घटाने में मदद करने और बुढ़ापा रोधी गुणों के लिए अच्छे हैं।और यह केवल उस फल का गूदा नहीं है जिसे देने के लिए लाभ हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि बीज, छिलका और पत्ते सभी में कई गुण होते हैं।अमरूद के पत्तों का अर्क दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक चिकित्सा का हिस्सा रहा है। उदाहरण के लिए, जापान औषधीय गुणों वाली हर्बल

चाय बनाने के लिए अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाता है।

यहाँ स्वस्थ चाय बनाने की विधि दी गई है:

1. चार बड़े ताजे अमरूद के पत्ते धो लें (एक परोसता है)

2. एक पैन में एक कप पानी गर्म करें और उसमें अमरूद के पत्ते डालें।3. इसे पांच मिनट तक उबलने दें।

4. पत्तों को छानकर पानी में आधा नींबू निचोड़ लें।

5. स्वादानुसार थोड़ा सा शहद मिलाएं।

6. इसे अच्छे से मिलाएं।

आपको क्यों अमरूद के पत्तों से चाय बनानी चाहिए जाने :

1. रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करता है
2. दस्त के इलाज में मदद करता है
3. वजन घटाने में मदद करता है
4. रोगाणुरोधी गुण
5. कोलेस्ट्रॉल कम करता है
6. रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है
7. मासिक धर्म में ऐंठन से राहत देता है

उत्तराखंड में नशे की लत के संबंध में, जानिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संयुक्त कार्य योजना

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देश में बच्चों में बढ़ती नशे की लत एक गंभीर समस्या बन चुकी है। भारत सरकार के इस सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि 10 से 17 वर्ष आयु समूह के लगभग 1.48 करोड़ बच्चे और किशोर अल्कोहल, अफीम, कोकीन, भांग सहित कई तरह के नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में आजा बच्चों को नशे की लत से दूर रखने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से एक विचार-गोष्ठी आयोजन किया गया. बच्चों में नशे की प्रवृत्ति को रोका जा सके और उन्हें नशे के दलदल में पड़ने से बचाया जा सके। इसके लिए संयुक्त कार्य योजना के तहत स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही हर स्कूल में बच्चों का एक छोटा सा प्रेशर ग्रुप बनाया जा रहा है.

जिन्हें शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना का कहना है कि राज्य में दवा की 80 फीसदी दुकानों पर सरकार की ओर से कैमरे लगवाए गए हैं, जो कफ सिरप और नींद की गोलियां बेच रहे हैं. दवाएं बेची जाती हैं। इसके अलावा दवाओं के स्टॉक को डिजिटाइज किया जा रहा है। ताकि यह देखा जा सके कि दवा की दुकान में किस तरह की खरीद या दवा का इंजेक्शन, नींद की दवा या कफ सिरप बेचा जा रहा है। डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि हर स्कूल में बच्चों का प्रेशर ग्रुप बना दिया गया है. जिसके तहत बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये बच्चे अपने शिक्षकों को सूचित करेंगे कि शायद यह बच्चा नशे की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण के बाद शिक्षक ऐसे बच्चे के व्यवहार को पहचान सकेंगे, जो नशे की चपेट में आ रहा है.

संपादकीय

राजनीति व अर्थव्यवस्था में घुन है मुफ्तखोरी

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकारों का विकास, गरीबी निवारण, बेहतर सामाजिक सेवाओं, पेयजल, सड़क, रेल निर्माण आदि पर जोर रहा, लेकिन अब कुछ राजनीतिक दल मुफ्त बिजली, पानी, यातायात, मुफ्त टेलीविजन और यहां तक कि मंगलसूत्र तक देने के वादे करने लगे हैं. सरकार की खराब आर्थिक स्थिति और बढ़ते कर्ज के बावजूद उन वादों को पूरा करने के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं. दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासी भी रहते हैं, जो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में बसे हुए हैं. दिल्ली में ऐसे प्रवासी मजदूरों की संख्या 20 लाख से कम नहीं है. जो मजदूर अपने परिवार को साथ लाते हैं, वे भी दयनीय अवस्था में रह रहे हैं. उनके परिवार के लिए स्कूल-कॉलेजों की जरूरत है. साथ ही, बेहतर जल-मल व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सड़कों, पुलों आदि की आवश्यकता है, लेकिन इन कार्यों के लिए भारी खर्च की जरूरत होती है. देखा जा रहा है कि खर्च के अभाव में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार विकास और रखरखाव के लिए भी धन नहीं जुटा पा रही है. साल 2015 में सत्ता संभालने के बाद से दिल्ली सरकार कोई नया स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फ्लाईओवर आदि बना नहीं पायी. दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय व राजस्व शेष भारत से काफी अधिक है और लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस राजस्व को मुफ्त बिजली, पानी और यातायात में खर्च कर देने के कारण आवश्यक नागरिक सुविधाओं हेतु धना का अभाव होता जा रहा है. दिल्ली का कुल राजस्व 2021-22 के लिए 53070 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो सभी राज्यों के राजस्व का तीन प्रतिशत है. बढ़ते राजस्व के साथ-साथ दिल्ली सरकार का मुफ्त बिजली, पानी, यातायात पर खर्च भी बढ़ता गया. मुफ्त बिजली पर खर्च 2015-16 में 1639 करोड़ रुपये था, जो 2021-22 में 2968 करोड़ रुपये पहुंच गया है. वर्ष 2022-23 के लिए विद्युत विभाग ने दिल्ली सरकार से बिजली सब्सिडी हेतु 3200 करोड़ रुपये की मांग की है. समझा जा सकता है कि दिल्ली सरकार द्वारा बिजली मुफ्त करने के नाम पर बजट पर बोझ बढ़ता जा रहा है. पानी के बिल को शून्य करने की कवायद में दिल्ली जल बोर्ड का घाटा और कर्ज दोनों बढ़ रहे हैं. केजरीवाल सरकार के पहले तीन साल में बोर्ड का घाटा 2015-16 में 220.19 करोड़ से बढ़ता हुआ 2018-19 में 663 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका था. दिल्ली सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जल बोर्ड को 41000 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये हैं. जल बोर्ड की बदतर स्थिति का अंदाजा धीमे विकास कार्यों और लचर जल व्यवस्था से लगाया जा सकता है. विपक्षी दल जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते रहे हैं.

देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने कोर्ट के लंबित मामलों को समय पर निस्तारण करने का दिया निर्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून,9 सितंबर। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा 10 बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने कोर्ट के लंबित मामलों के साथ एवं तहसीलदारों को अपने-अपने कोर्ट में चल रहे प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को अविवादित विरासत के मामलों पर अभियान चलाकर निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिये। वहीं अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराये भूमि पर बोर्ड लगाना के निर्देश देते हुए, अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध सघन अभियान चलाने को कहा। जबकि सभी उपजिलाधिकारी को अपने अपने क्षेत्रान्तगत डेंगी (डेगूं) को लेकर रेखीय विभाग के साथ बैठक करते हुए, जन सहभागिता के साथ जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। और कहा कि धरातल पर कार्य दिखाई देनी चाहिए। सभी इस बात को गम्भीरता से लेगें।जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि आवेदकों द्वारा आवेदन की गई प्रमाण पत्रों को प्राथमिकता से लेते अपने स्तर पर त्वरित निस्तारण करेंगे। ताकि लोगों को समय पर अपनी दस्तावेज प्राप्त होने पर वे सुविधा ले सकें।

लंबित मजिस्टेªट जांच पर उपजिलाधिकारियों को निर्देश किया कि अपने क्षेत्र के मजिस्टेªट जांच को शीध्र निस्तारित करें। उन्होंने भूमि वाद, 33/39,176, 29 ब, सहित अन्य मामलों की तहसील वार अद्यतन जानकारी लेते हुए, प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उपजिलाधिकारी चकराता द्वारा तहसील में पेशकार नही होने की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी ने तहसील चकराता में पेशकार भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य देय की वसूली प्रत्येक दशा में शत प्रतिशत करने तथा विविध देयों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए वसूली पर कडी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेंशन प्रकरण के लम्बित प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को भूमि रजिस्ट्री की डुप्लीकेसी रोकने, भूमि संबंधित विवादों, म्यूटेशन के मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश दिए। उन्होंने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में सभी सरकारी राशन की दुकानों में बायोमेट्रिक के द्वारा राशन वितरण किया करने तथा चकराता में बायोमेट्रिक बढाने के निर्देश के साथ कहा कि जनपद में राशन वितरण पर तहसील वार डिजिटल ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन की दुकानों तथा गोदामों का औचक निरीक्षण किया जाए। उन्होने पटल प्रभारी को समस्त तहसीलों से निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट मांगने को कहा तांकि जिला मुख्यालय में पहुंचने वाले रिपोर्ट में त्रुटि रहित एकरूपता बनी रहे। बैठक में अपर जिलाधिकारी के. के मिश्रा उपजिलाधिकारी सदर मायाराम जोशी, तहसीलदार सोहन सिह रांगड, सहित कलेक्ट्रेट के अधिकारी/कार्मिक कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित रहे तथा उप जिलाधिकारी शैलेन्द्र नेगी, सौरभ असवाल, विनोद कुमार एवं युक्ता मिश्र एवं तहसीलदार आदि ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।

उच्च शिक्षा में इस सत्र से लागू होगी एनईपी: डॉ0 धन सिंह रावत

आशीष तिवारी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून/नई दिल्ली, 10 सितम्बर , उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने के बाद अब इसी माह उच्च शिक्षा विभाग में भी एनईपी लागू कर दी जायेगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। इस बात की जानकारी सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दी। उन्होंने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को उच्च शिक्षा विभाग में एनईपी-2020 लागू करने के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि अमंत्रित किया। जिस पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने अपनी सहमति दी है।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टचार भेंट की। इस दौरान डॉ0 रावत ने केन्द्रीय मंत्री से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, पीएम-श्री योजना सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। डॉ0 रावत ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां विद्यालयी शिक्षा में एनईपी को लागू कर दिया गया है, जिसकी सराहना देशभर में हो रही है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा में भी इसी सत्र से सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर एनईपी लागू कर दी जायेगी। जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। डॉ0 रावत ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के शुभारम्भ केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कर कमलों से किया जायेगा। इसके लिये देहरादून में माह सितम्बर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। पीएम-श्री योजना के तहत देशभर के 14500 विद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाये जाने पर उन्होंने केन्द्रीय मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम-श्री योजना से न सिर्फ पिछड़े क्षेत्रों के स्कूलों की सूरत बदलेगी बल्कि छात्र-छात्राओं को बेहत्तर शिक्षा मुहैया हो सकेगी। केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान डॉ0 रावत ने एच0एन0बी0 गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कार्मिकों की विभिन्न मांगों पर भी चर्चा की, साथ ही एनआईटी सुमाडी में चल रहे निर्माण कार्यों से भी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को अवगत कराया।

फर्जी मुकदमों में फंसवाने वाले गुनहगारों से सावधान

बिना जांच के बेगुनाहों के विरुद्ध सीधे मुकदमे कराने और गिरफ्तारी की भी ले लेते है गारंटी.?

मो.सलीम सैफी
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 9 सितंबर। मुख्यमंत्री धामी का स्पष्ट कथन है कि किसी भी बेगुनाह के साथ धामी-राज में कभी भी,किसी भी रूप में,किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा और पापी बच नही पाएगा यानी मुख्यमंत्री ने साफ़ संकेत दिए है कि किसी भी तहरीर को केस के रूप में रजिस्टर्ड करने से पहले निष्पक्ष जांच पड़ताल गहराई से ज़रूर कर ली जाए ताकि किसी भी बेगुनाह के साथ अन्याय न हो, लेकिन लगता है कि राजधानी देहरादून में आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है किसी भी बेगुनाह शख्स को फर्जी मुकदमों में फंसवाने का, झूंठे केसो में उलझाने का,किसी भी हाई प्रोफाइल केस में चुपके से किसी का भी नाम सरकाने का और ये सब होता है पूर्वनियोजित ढंग से,ये वो लोग होते है जो आपके आसपास के लोग होते है जिनसे किसी न किसी रूप में आपका आर्थिक लेनदेन हुआ होता है या फिर किसी भी लेनदेन की उनको जानकारी होती है या उन गुनहगारों ने कभी न कभी आपके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई आर्थिक व्यवहार किया हो।

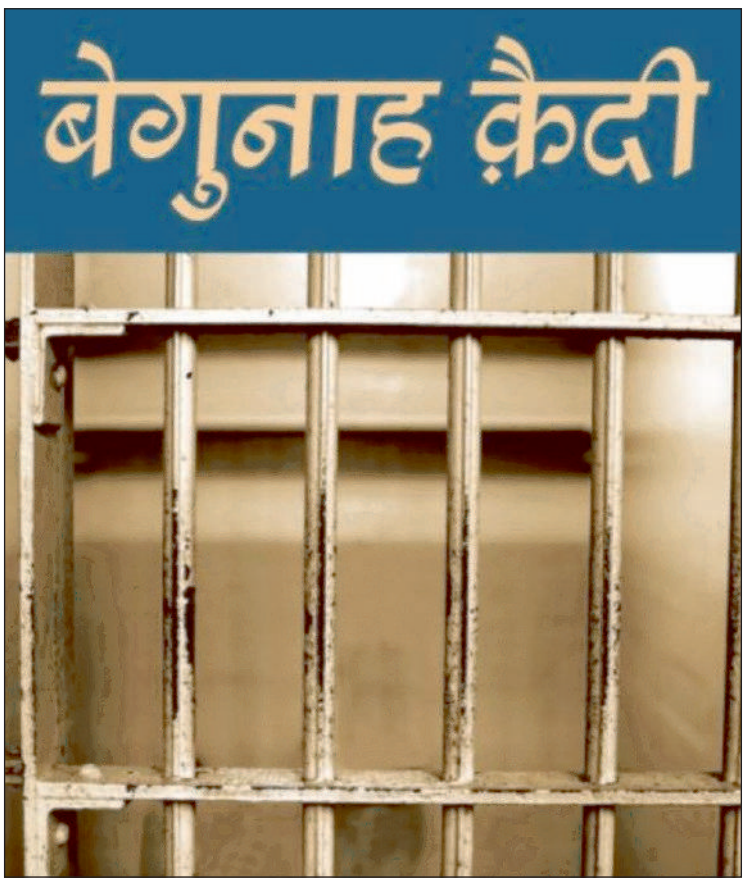

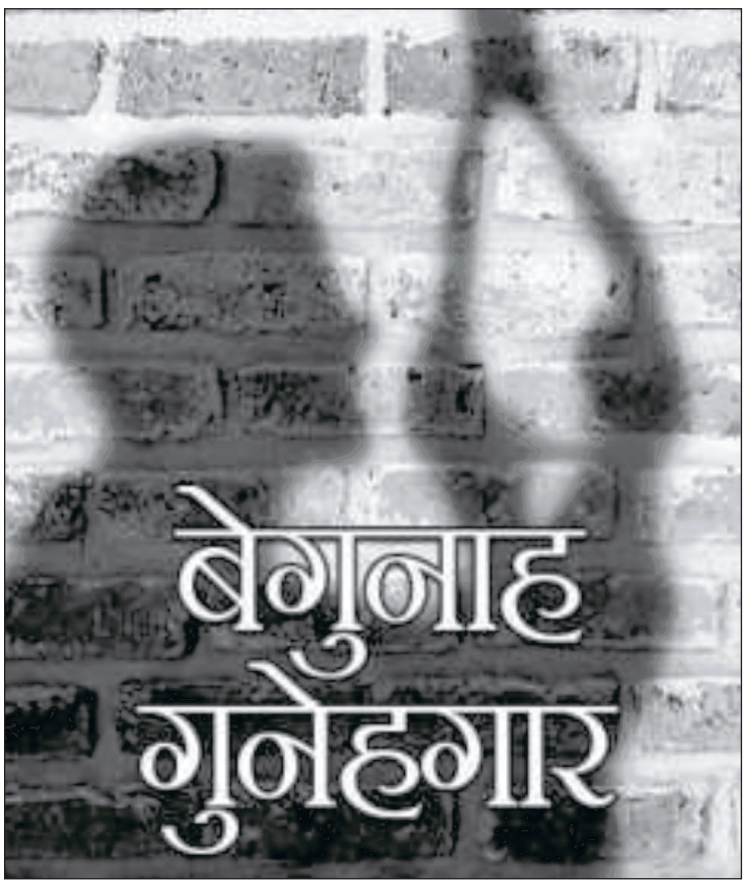

अब हम बताते है कि ये गुनहगार सक्रिय कैसे होते है,इनका सबसे आसान टारगेट होते है वो लोग जो इनको रुपया पैसा उधार देते है,जब तक इनसे पैसा वापस नहीं मांगा जाता तब तक ये गुनहगार बहुत व्यवहारिक और शरीफाना अंदाज़ अपनाते है,जैसे ही उधार देने वाला शख्स या आर्थिक व्यवहार करने वाला शख्स अपना पैसा वापस मांगता है तो ये अपने असली रूप में आ जाते है अर्थात फर्जी पुलिस केस बनवाने का प्रयास करते है, कभी कभी ये ठग अपने नापाक प्रयासों में कामयाब भी हो जाते है तो कभी कभी एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर जैसे काबिल अफसरों की पैनी नज़र इनके नापाक इरादों को वक्त रहते पहचान लेती है और कोई भी बेगुनाह इनका शिकार होने से बच जाता है।

राजधानी देहरादून हो या फिर छोटे छोटे शहर और कस्बे हर जगह ऐसे गुनहगार कुछ कथित पत्रकारों को मोटी आमदनी कराने के नाम पर साथ जोड़े रखने का इरादा भी परवान चढ़ाते है, कही इन्हे कामयाबी मिलती है तो कही मायूसी इनके हाथ आती है,इन कथित पत्रकारों की भूमिका सिर्फ़ माहौल बनाना और कही दबाव की कोशिश करना भी होता है हालकि असली लाभ तो गुनहगारों को ही होना ही प्रतीत होता है,कथित पत्रकार तो छोटे लालच की बुनियाद पर अनजाने में जानबूझकर किसी भी बेगुनाह को फसवानें का गुनाह करने से बाज़ नही आता और वो ये भूल जाता है कि उसकी इस नादानी से किसी भी बेगुनाह शख्स की उम्रभर की इज़्ज़त दाव पर लग जाती है और वो फिर मजलूम से जालिम बनने को मजबूर हो जाता है हालकि सच और गुनाह कभी न कभी सामने आते ही है,कभी छुप नहीं सकते। ऐसे गुनहगार अपने घर की इज़्ज़त की परवाह किए बिना अनैतिक और असंवैधानिक कृत्य करने से भी बाज़ नही आते,अपनी सम्मानित पत्नी,बहन या किसी अन्य से भी कोई भी इल्ज़ाम किसी भी बेगुनाह को फंसवाने के लिए लगवा देते है। अगर आप पुलिस के पास आने वाली तहरीरों पर एक अध्यन करेंगे तो चौंक जाएंगे ज्यादातर की गहराई से जांच करने पर कही न कही ऐसे कथित शिकायतकर्ता की शिकायत में आपको झोल ही झोल मिलेंगे और कही न कही आर्थिक हित भी छुपे होंगे। कुल मिलाकर किसी भी पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी को आंख बंद करके किसी भी तहरीर या सूचना को पूर्णता सच मानकर किसी भी बेगुनाह को गुनहगार साबित करने पर आमादा नही होना चाहिए अर्थात वो पाप करने से हर किसी को परहेज़ करना चाहिए जिससे उसकी आत्मा भी परमात्मा के सामने शर्मिंदा न हो।

वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने दिया 28 सितंबर तक का समय

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

नैनीताल, 9 सितम्बर । खटीमा के आरक्षित वन क्षेत्र सालबोझी में वन विभाग की जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार और वन विभाग को 28 सितंबर तक अदालत को यह बताने को कहा है कि उत्तराखंड में पट्टे के नवीनीकरण के क्या नियम हैं। ऐसे में इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तारीख तय की गई है।

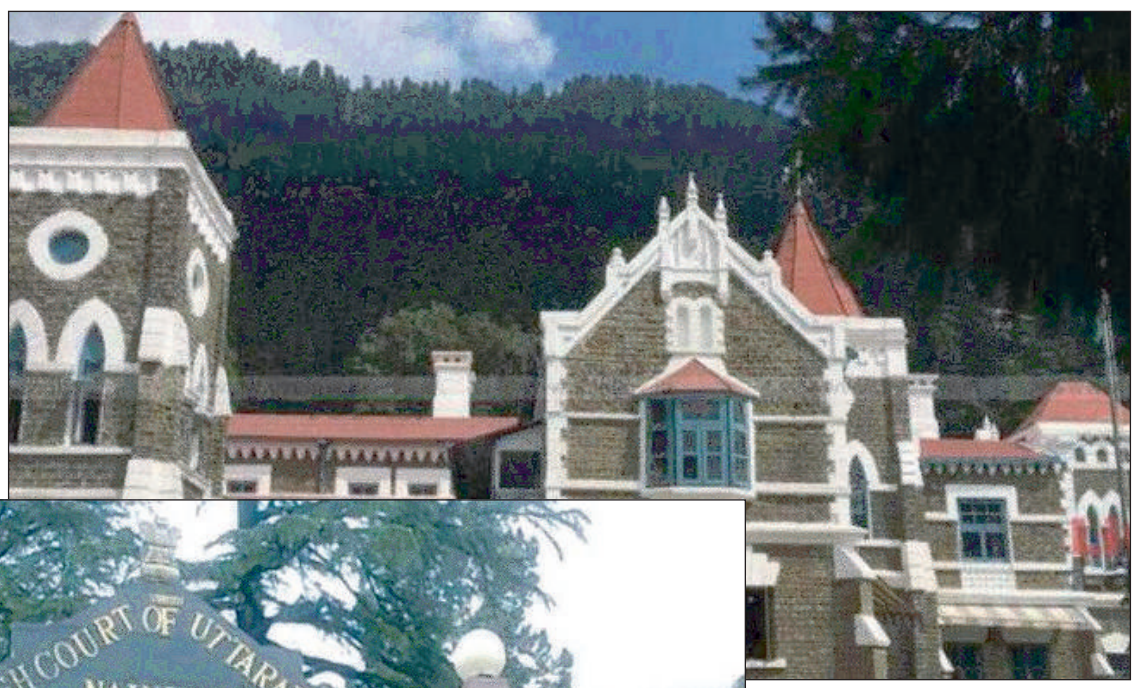

खटीमा निवासी शुभम अग्रवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सालबोझी में एक में 29 और दो में 11 लोगों ने पिछले 30 साल से खटीमा के आरक्षित वन क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है. पहले ये पट्टे वन विभाग द्वारा उन्हें 1975-1978 के बीच एक वर्ष के लिए लीज पर दिए जाते थे, जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। वहीं लीज खत्म होने के बाद भी वन भूमि पर कब्जा कर लिया है। वहीं, 2015 में उनके द्वारा लीज बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें हाईकोर्ट ने वन विभाग को उनके अभ्यावेदन का निस्तारण करने का निर्देश दिया था। लेकिन आज तक वन विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही अतिक्रमण हटाया गया. याचिकाकर्ता का कहना है कि वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।

दैनिक
न्यूज वायरस
न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।
सम्पादक:
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002
email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094
वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा